

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
संस्कृत शिक्षा,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 24 अगस्त 2009

विषय:- वित्तीय वर्ष 2009-10 में संस्कृत शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आय-व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-515/XXVII(I)/2009, दिनांक 28 जुलाई 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में संस्कृत शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए आयोजनागत पक्ष में रु० 6877 हजार एवं आयोजनेत्तर पक्ष में रु० 119221 हजार, इस प्रकार कुल रु० 125098 हजार (रुपये बारह करोड़ पचास लाख अठानवे हजार मात्र) की धनराशि, को इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वचनबद्ध मदों में यथा वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, मजदूरी, विद्युत देय, जलकर, किराया, पेंशन, औषधि, भोजन व्यय, पेट्रोल, टेलीफोन आदि आवश्यक व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों हेतु स्वीकृति का प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

2- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आबंटित परिव्यय की सीमा तक किये जाने का दायित्व आपका होगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा:-

- 1- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- 2- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा

- बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
- 3- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
  - 4- आबंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय।
  - 5- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
  - 6- व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।
  - 7- स्वीकृत धनराशि की जिलावार फॉट सम्बन्धित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
  - 8- वित्तीय वर्ष 2009-10 में इसके पूर्ववर्ती वर्षों के एरियर भुगतान यदि कोई हो, के विवरण की सूचना अलग से रखी जाय।
  - 9- अप्रैल, 2009 से नये पदों के भरे जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय के सापेक्ष श्रेणीवार पदों (समूह "क" "ख" "ग" व "घ") की सूचना रखी जाय।
  - 10- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुवल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
  - 11- निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/ पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों की लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण अनिवार्य रूप से किया जाय।
  - 12- किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
  - 13- बजट मैनुवल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जानी वाली सूचना समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
  - 14- वाह्य सहायतित परियोजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए ट्राइबल सबप्लान के अन्तर्गत आवंटित परिव्यय के सापेक्ष बजट प्राविधान को अन्य योजना हेतु व्यावर्तित न किया जाय।

- 15— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पाँच भाग-1 (लेखा नियम) आय-व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों, आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 16— यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय-व्यय 2009-10 में बजट प्राविधान लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय-व्यय के प्राविधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।
- 3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा"-05-भाषा विकास-के सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।
- 4— यह आदेश वित्त विभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 515 XXVII(I)/2009, दिनांक 28 जुलाई 2009 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।  
संलग्नक— यथोपरि।

भवदीय,  
(शत्रुघ्न सिंह)  
सचिव।



संख्या:सं०।१०(1) /XXIV-4/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
- 6- आयुक्त कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल-पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10- सचिव, उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
- 12- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 13- वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 15- कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
- 16- एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(पी०एल०शाह)  
उप सचिव।